



भारत का राजपत्र The Gazette of India

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 288]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 9, 2014/अग्राहायण 18, 1936

No. 288]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 9, 2014/AGRAHAYANA 18, 1936

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसंबर, 2014

विषय : चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित मलबरी कच्चे रेशम के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए जांच की शुरूआत

संख्या 14/17/2014-डीजीएडी.—मै. सेंट्रल सिल्क बोर्ड (जिसे आगे याचिकाकर्ता या आवेदक भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात नियमावली कहा गया है), के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें चीन जन.गण. (जिसे एतदपश्चात संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 3-ए ग्रेड या उससे नीचे के मलबरी कच्चे रेशम (नॉट थ्रोन) (जिसे एतदपश्चात संबद्ध वस्तु या पीयूसी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है।

विचाराधीन उत्पाद

2. संबद्ध जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद 3-ए ग्रेड या उससे नीचे के मलबरी कच्चा रेशम (नॉट थ्रोन) है। कच्चे रेशम को कपड़े में बुना जाता है। इस रेशम को पाले गए (सेरीकल्चर) मलबरी रेशम के कीड़े बॉम्बिक्स मोरी के लारवा के कोकूनों से प्राप्त किया जाता है। रेशम मुख्यतः फाइबोरिन वाला प्रोटीन फाइबर होता है और इसे कोकून बनाने के लिए लारवा कीट द्वारा बनाया जाता है। रेशम का चमकीला स्वरूप रेशम के तार के त्रिभुजाकार पिज्म जैसे ढांचे के कारण होता है जिससे रेशम का कपड़ा अलग-अलग दिशाओं से आने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है और इससे विभिन्न रंग उत्पन्न होते हैं। रेशम का उत्पादन अनेक अन्य कीटों से भी होता है परंतु आम तौर पर मोथ कैटरपिलर्स के रेशम का ही उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। घरेलू उद्योग ने बताया है कि कोई अनिवार्य विनिर्देशन या मानक नहीं होते हैं। तथापि, अंतर्राष्ट्रीय सिल्क

एसोसिएशन (आईएसए) के कच्चा सिल्क परीक्षण और वर्गीकरण मानक पुस्तिका में ग्रेडिंग प्रणाली बताई गई है और उसे वैश्विक रूप से स्वीकार किया जाता है।

संबद्ध वस्तुओं को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 50 के अंतर्गत और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वर्गीकरण के अनुसार 5002.00.10 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

4. याचिकाकर्ता ने बताया है कि भारत में चीन जन.गण. से निर्यातित 3-ए ग्रेड या उससे नीचे के मलबरी कच्चे रेशम (नॉट थ्रोन) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और चीन जन.गण. से आयातित 3-ए ग्रेड या उससे नीचे के मलबरी कच्चे रेशम (नॉट थ्रोन) भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन आदि जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय है। उपभोक्ता इनका एक-दूसरे के स्थान पर उपयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

5. केन्द्रीय सिल्क बोर्ड ने कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों में अपनी 9 एसोसिएशनों/सोसायटियों के माध्यम से घरेलू उत्पादकों/रीलर्स की ओर से एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें 3-ए ग्रेड या उससे नीचे के मलबरी कच्चे रेशम (नॉट थ्रोन) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है। एसोसिएशनों/सोसायटियों ने पाटनरोधी जांचकी शुरुआत के लिए वर्तमान आवेदन दायर करने हेतु सीएसबी (आवेदक) को विधिवत रूप से प्राधिकृत किया है। इन एसोसिएशनों/सोसायटियों को उनके संघटक सदस्यों, जो उत्पादक/रीलर हैं, ने प्राधिकृत किया है।

याचिकाकर्ता ने प्रमाणित किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा या उसके किसी संबद्ध पक्षकार द्वारा संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात नहीं किया गया है। चूंकि याचिकाकर्ता का उत्पादक भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, इसलिए याचिकाकर्ता नियमावली के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग की स्थिति को पूरा करता है और घरेलू उद्योग है।

शामिल देश

6. वर्तमान जांच चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन से संबंधित है।

सामान्य मूल्य

7. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि चीन जन.गण. को गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और उसने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। गैर बाजार अर्थव्यवस्था मान्यता और प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा उसके खंडन के अधीन चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार अनुमानित किया गया है। आवेदक ने भारत में उत्पादन लागत जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों तथा तर्कसंगत लाभ के लिए विधिवत रूप से समायोजित किया गया है के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

निर्यात कीमत

8. आवेदक ने आईबीआईएस द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की है। कमीशन, समुद्री भाड़ा, पत्तन व्यय, अंतरदेशीय भाड़ा, समुद्री बीमा, और बैंक प्रभारों के लिए कीमत समायोजनों का दावा किया गया है।

पाटन मार्जिन

9. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना द्वार स्तर पर की गई है जिससे संबद्ध देश के संबंध में भारी पाटन मार्जिन प्रदर्शित होता है। इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना द्वार निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है कि संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

क्षति और कारणात्मक संबंध

10. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से वास्तविक क्षति उठानी पड़ी है। क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पादकी मांग में वृद्धि हुई है और संबद्ध आयातों में समग्र रूप से वृद्धि हुई है। आयातों के कारण घरेलू कीमतों में कटौती हुई है। आयातों में क्षति अवधि के कारण घरेलू कीमत को कम/न्यून किया है। घरेलू उद्योग पर आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में लाभ, नियोजित पूंजी पर आय और नकद लाभ जैसे मापदंडों की दृष्टि से विकृति आई है। घरेलू उद्योग भारी वित्तीय घाटे, नकद घाटे और निवेशों पर नकारात्मक आय का सामना कर रहा है। संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति होने का पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य है जो पाटनरोधी जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराता है।

11. और यतः प्राधिकारी प्रथमदृष्टया पाते हैं कि संबद्ध देश के मूल की या अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति के पर्याप्त साक्ष्य हैं और कथित पाटन तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध मौजूद है जो पाटनरोधी जांच की शुरुआत को सही ठहराता है। अतः प्राधिकारी एतद्वारा नियमावली के पैरा 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जांच की शुरुआत करते हैं ताकि पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाय तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

जांच अवधि

12. जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2013 से 30 जून, 2014 तक (15 महीने) की है। तथापि क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ पिछले तीन वर्षों अर्थात् अप्रैल 2010 से मार्च 2011, अप्रैल, 2011 से मार्च 2012, अप्रैल 2012 से मार्च 2013 और जांच अवधि के आंकड़ों पर विचार किया गया है।

सूचना प्रस्तुत करना

13. संबद्ध देश में निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकार, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने और निम्नलिखित पते पर प्राधिकारी को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है:-

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य विभाग
जीवन तारा बिल्डिंग, चौथा तल
5, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001

14. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना संबंधी कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों के लिए उसका अगोपनीय अंश उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

समय-सीमा

15. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

16. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें। यह सूचना मूल प्रतियों तथा सॉफ्ट प्रतियों में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

17. प्रश्नावली के उत्तर समेत प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उनके साथ संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) करने वाले पक्षकारों को "गोपनीयता" का दावा करने के मामले में :-

(क) गोपनीय रूप से अंकित (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) और

(ख) अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) में दो अलग-अलग सैटों में सूचना प्रस्तुत करनी चाहिए।

18. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों में प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे चिन्हांकन के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी के पास ऐसे अनुरोधों का अन्य पक्षकारों को निरीक्षण करने देने की अनुमति देने की स्वतंत्रता होगी। दोनों संस्करणों की सॉफ्ट कॉपी भी मूल प्रतियों के साथ-साथ प्रत्येक के दो (2) सैटों में प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है।

19. गोपनीय रूपांतरण में ऐसी समस्त सूचना होनी चाहिए जो स्वभाविक रूप से गोपनीय है और/या अन्य सूचना जिसे उस सूचना का प्रदाता गोपनीय होने का दावा करता है। गोपनीय रूप में दावा की गई सूचना या अन्य कारणों की वजह से दावा की गई गोपनीयता वाली सूचना के लिए सूचना प्रदाता के लिए यह अपेक्षित है कि वह प्रदान की गई सूचना के साथ इस आशय के यथोचित कारण का एक विवरण उपलब्ध कराए कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता।

20. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई/सारांशीकृत गोपनीय सूचना (जहां सूचीबद्ध करना संभव न हो) के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है; तो प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

21. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

22. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी रिकॉर्ड में नहीं लेंगे।

23. संतुष्ट होने और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत को स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार का उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

24. नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

25. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

जे.के. दादू, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2014

Subject: Initiation of investigation for imposition of anti-dumping duty on imports of Mulberry Raw Silk originating in or exported from China PR.

F.No.14/17/2014-DGAD.— M/s. Central Silk Board (hereinafter also referred to as the Petitioner or applicant) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti dumping duty on the imports of Mulberry Raw Silk (not thrown) of 3A grade and below (hereinafter also referred to as the subject goods or PUC) , originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the subject country).

Product under consideration

2. The product under consideration for the purpose of subject investigation is 'Mulberry Raw Silk (not thrown) of 3A grade and below'. Raw silk is woven into textiles. The silk is obtained from the cocoons of the larvae of the mulberry silkworm *Bombyx mori* reared in captivity (sericulture). The silk is a protein fibre composed mainly of fibroin and produced by the insect larvae to form cocoons. The shimmering appearance of silk is due to the triangular prism-like structure of the silk fibre, which allows silk cloth to refract incoming light at different angles, thus producing different colors. Silks are produced by several other insects, but generally only the silk of moth caterpillars has been used for textile manufacturing. Domestic industry has submitted that there are no mandatory specifications or standards. However, the grading system is described in the standard manual of Raw Silk Testing & Classification of the International Silk Association (ISA) and is universally accepted.

The subject goods are classified under Chapter 50 of the Customs Tariff Act, 1975 and further under 5002.00.10 as per International Trade Classification. The classification, however, is only indicative and in no way binding on the scope of the present investigation.

Like Article

4. The petitioner has submitted that Mulberry Raw Silk (not thrown) of 3A grade and below, which is exported from China PR into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. Mulberry Raw Silk (not thrown) of 3A grade and below produced by the domestic industry and imported from China PR is comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing etc. Consumers can use and are using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant in India are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject country.

Domestic Industry & Standing

5. Central Silk Board has submitted an application on behalf of the domestic producers/reelers through their nine associations/societies in the States of Karnataka, Tamil Nadu and Andhra Pradesh for imposing antidumping duty on imports of Mulberry Raw Silk (not thrown) of 3A grade and below. The associations/societies have duly authorized CSB (applicant) to file the present application for initiation of the anti-dumping

investigation. These associations/ societies have been authorized by their constituent members who are the producers/reelers.

The petitioner has certified that there are no imports of the product under consideration by the petitioner or any of its related party from the subject countries. Since the production of the petitioner accounts for “a major proportion” in the total production of the product under consideration in India, the petitioner satisfies the standing and constitutes Domestic Industry within the meaning of the Rules.

Countries involved

6. The present investigation is in respect of alleged dumping of the product under consideration from China PR.

Normal Value

7. The petitioner has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and has determined normal value in accordance with Para 7 and 8 of Annexure I of the Rules. In view of the non-market economy presumption and subject to rebuttal of the same by the responding exporters, normal value of the subject goods in China PR has been estimated in terms of Para 7 of Annexure I to the Rules. The applicant has determined the normal value based on cost of production in India, duly adjusted with selling, general and administrative expenses and reasonable profit.

Export Price

8. The applicant has determined the export price on the basis of data published by IBIS. Price adjustments have been claimed on account of commission, ocean freight, port expenses, inland freight, marine insurance, and bank charges.

Dumping Margin

9. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which show significant dumping margin in respect of the subject country. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject country is significantly higher than the ex-factory export price, indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country.

Injury and Causal Link

10. The applicant has claimed that domestic industry has suffered material injury from dumped imports. The demand for the product under consideration has increased over the injury period and subject imports have increased in absolute terms. The imports are undercutting the domestic prices. The imports have suppressed/depressed the domestic prices over the injury period. With regard to consequent impact of the imports on the domestic industry, it is noted that performance of the domestic industry has deteriorated in respect of parameters such as profits; return on capital employed and cash profits. The domestic industry is suffering significant financial losses, cash losses and negative return on investments. There is sufficient prima facie evidence of injury to the domestic industry caused by dumped imports from subject country to justify initiation of an anti-dumping investigation.

11. And whereas, the Authority prima facie finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject country; injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury exist to justify initiation of an anti-dumping investigation, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Para 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the ‘injury’ to the domestic industry.

Period of Investigation (POI)

12. The period of investigation (POI) is from 1st April 2013 to 30th June 2014 (15 months). However, for the purpose of analyzing injury, the data of previous three years, i.e. Apr’10-Mar’11, Apr’11-Mar’12, Apr’12-Mar’13 and the period of investigation will be considered.

Submission of Information

13. The exporters in the subject country, their government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
Department of Commerce,
Jeevan Tara Building, 4th Floor
5, Parliament Street
New Delhi -110001

14. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time Limit

15. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.

16. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application within forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. The information must be submitted in hard copies as well as soft copies.

Submission of information on confidential basis

17. The parties making any submission (including Appendices/Annexure attached thereto), before the authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:-

- (a) one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and
- (b) the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).

18. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in two (2) sets of each.

19. The confidential version shall contain all information which are by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. The information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information can not be disclosed.

20. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient

detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

21. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

22. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

23. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

24. In terms of Rule 6(7) of the AD Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

25. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

J. K. DADOO, Designated Authority